www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 92 | जौनपुर, गुरूवार, 19 नवम्बर 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस–आप समेत इन संगठनों को भेजा नोटिस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। व्यापारिक संगठनों ने याचिका दाखिल कर मैदान में प्रदर्शन आयोजित करने पर रोक लगाने की मांग की है। व्यापारियों का दावा है कि लगातार होने वाले धरना–प्रदर्शनों के कारण आसपास के बाजारों और उनके कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने संशोधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) समेत कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को नोटिस जारी किया है।सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों की याचिका पर कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) को नोटिस भेजा है। इन संगठनों से मामले में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। याचिका में रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शनों से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने का मुद्दा उठाया गया है। व्यापारियों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़, यातायात में बाधा और आसपास की गतिविधियों पर असर के चलते दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी आधार पर उन्होंने प्रदर्शन को नियंत्रित करने या उस पर रोक लगाने की मांग की है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है।

यूपी में ओवैसी–चंद्रशेखर गठबंधन की कितनी ताकत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर राज्य की राजनीति में एक नए विकल्प की संभावना पेश की है. दोनों नेताओं ने अपने गठबंधन को श्सामाजिक परिवर्तन मोर्चाश नाम दिया है और ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया है. दोनों दलों ने राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर ला पाएगा और क्या इन दोनों समुदायों की एकजुटता उत्तर प्रदेश में एक नई चुनावी ताकत बन सकती हैओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस– ए–इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश कर रही है. वहीं, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) दलित राजनीति में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही है. चंद्रशेखर 2024 के लोकसभा चुनाव मेंनगीना सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को करीब डेढ़ लाख वोटों से हराया था. इस जीत ने उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ाई है. लेकिन लोकसभा की एक सीट पर बड़ी जीत को पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर समर्थन में बदलना इतना आसान नहीं होगा।

केंद्र ने सही नीतियों से बीते 12-13 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला- पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों की कार्यशैली पर निशाना साधा और उद्योग जगत को भरोसे का बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार पुरानी सरकारों की तरह नहीं है, बल्कि यह उद्योग जगत की 'दोस्त सरकार' है, जो दोस्ती निभाना जानती है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने अपनी सही नीतियों से केवल बीते 12–13 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सम्मेलन में उपस्थित उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए



पीएम मोदी ने दावा किया कि केंद्र सरकार की सही नीतियों के चलते महज बीते 12–13 वर्षों में देश के करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। 1970 के दशक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौर में जब 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया गया था, तब भारत की कुल आबादी ही लगभग 50 करोड़ थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय भी गरीबी खत्म की जा सकती थी, लेकिन फिक्की इस बात का गवाह है कि तब की नीतियों और इरादों दोनों में कमी थी। इसके विपरीत, वर्तमान सरकार ने सही नीति और नीयत के साथ काम करके यह बदलाव संभव कर दिखाया है। उद्योग जगत के पुराने अनुभवों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के साथ उद्योगपतियों का अनुभव इतना कड़वा रहा है कि उसका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। खुद को उद्योग जगत का सच्चा मित्र बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, "यह पुरानी सरकार नहीं, दोस्त सरकार है। इसलिए बिना किसी संकोच या झिझक के मुझे खुलकर लिखकर भेजें कि देश में अभी और किन सुधारों की आवश्यकता है।" उन्होंने कहा कि आज देश 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है और सरकार उद्योगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह तैयार है।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का शहरी विकास विभाग 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 का आयोजन करेगा। ये पुरस्कार केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में 52 पुरस्कार और 5 विशेष सम्मान प्रदान किए जाएंगे। इनके माध्यम से रेहड़ी–पटरी विक्रेताओं की आजीविका को सशक्त बनाने तथा वित्तीय समावेशन, डिजिटल सेवाओं को अपनाने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीएस), ऋण देने वाली संस्थाओं और सहयोगी संगठनों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया जाएगा। इस योजना से जुड़े विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 600 प्रतिभागियों के इस आयोजन में शामिल होने की उम्मीद है। 1 जून 2020 को शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से अब तक लगभग 81 लाख रेहड़ी–पटरी विक्रेताओं को 1.21 करोड़ से अधिक ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी कुल राशि लगभग 20,000 करोड़ रुपये है। अगस्त 2025 में सरकार ने इस योजना का पुनर्गठन किया और इसकी कार्यान्वयन अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी। योजना का दायरा बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को और मजबूत करने के लिए इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। ऋण राशि में वृद्धिरू रेहड़ी–पटरी विक्रेताओं की बदलती ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण की तीनों किस्तों की राशि में वृद्धि की गई है।



बजट 2027–28 की तैयारी तेज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आइटी सेक्टर के साथ की छठी चर्चा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकीक्षेत्र के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ छठी बजट–पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक केंद्रीय बजट 2027–28 की तैयारियों के तहत आयोजित की गई। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, नीति आयोग के सीईओ, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए। यह बैठक बजट पेश किए जाने से पहले अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव और राय लेने की सरकार की वार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके तहत उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को आर्थिक प्राथमिकताओं पर अपने विचार रखने और आगामी बजट में ध्यान दिए जाने वाले मुद्दों को सामने रखने का अवसर मिलता है। इस बैठक के साथ सरकार ने बजट 2027–28 से पहले परामर्श के छह दौर पूरे कर लिए हैं। इनमें अर्थशास्त्रियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों स्टार्टअप, पूंजी बाजार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ चर्चा की गई है। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने पूंजी बाजार और क्षेत्र के हितधारकों के साथ पांचवीं बजट–पूर्व बैठक की अध्यक्षता की थी। चौथी बैठक डैडम क्षेत्र और स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी, जबकि तीसरी बैठक में विशेषज्ञों और उद्योग जगत के नेताओं ने हिस्सा लिया था।



गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में आतंकवाद – रोधी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में दो दिवसीय 'आतंकवाद–रोधी सम्मेलन' का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में इस वर्ष 'सीमा–पार आतंकवाद' विषय पर विशेष रूप से विचार–विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ देश की सामूहिक प्रतिक्रिया को मजबूत करना और उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना है। हर वर्ष आयोजित होने वाला यह सम्मेलन सुरक्षा बलों, आतंकवाद–रोधी एजेंसियों और



तकनीकी, कानूनी एवं फॉरेंसिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान करता है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर सामूहिक रूप से विचार–विमर्श किया जाता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ समन्वित और प्रभावी कार्रवाई के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक संवाद के माध्यम विकसित करना और भविष्य की नीतियों के निर्माण में ठोस योगदान देना है। सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में विदेशी न्यायक्षेत्रों से साक्ष्य प्राप्त करने, आतंकवादी मामलों की जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण के इस्तेमाल तथा मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कट्टरपंथ का मुकाबला करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने उभर रहे हाइब्रिड खतरों से निपटने के उपायों पर भी विचार–विमर्श किया जाएगा। अन्य सत्रों में आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों, तकनीकों और विभिन्न मामलों से मिले अनुभवों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद–रोधी रणनीतियां विकसित करने और सुरक्षा एजेंसियों की संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी।

भारत-इटली साझेदारी को नई ऊंचाई देने का समय, कारोबार और तकनीक में सहयोग पर जोर - पीयूष गोयल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय नवाचार और इतालवी उद्यम एक–दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया। गोयल ने रोम में आयोजित चौथे भारत–इटली बिजनेस एंड इनोवेशन फोरम के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कारोबारियों से पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर आर्थिक और तकनीकी साझेदारी के नए क्षेत्रों में अवसर तलाशने का आह्वान किया। इस दौरान उनके साथ इटली के उपप्रधानमंत्री और विदेश एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी भी मौजूद रहे।



उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में 49.6 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ते मध्यम वर्ग, युवाओं की आकांक्षाओं और आय में वृद्धि के साथ भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक साझेदारियों के लिए अपने दरवाजे और अधिक खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने भारत की तकनीकी और औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 50 अरब डॉलर के निवेश और 2030 तक सालाना 130 अरब डॉलर की अनुमानित खपत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भविष्य की तकनीकों के लिए तैयारी कर रहा है। रोम में इंडिया–इटली इनोवेशन फोरम के दौरान स्टार्टअप प्रतिनिधियों से बातचीत में गोयल ने कहा कि देश के अलग–अलग हिस्सों से कई भारतीय स्टार्टअप प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने। उन्हें इतालवी कंपनियों और कारोबारियों से बातचीत करने तथा नेटवर्किंग का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के स्टार्टअप ने अपने विचारों को कारोबार में बदलने के अनुभव साझा किए। उन्होंने भारतीय और इतालवी स्टार्टअप से एक–दूसरे के बाजारों में साझेदारी करने और अपने कारोबार का विस्तार करने का आग्रह किया।

राहुल गांधी के अमेरिकी बयान से सियासी घमासान, किरेन रिजिजू ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में भारतीय अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयानों पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत में रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए कहा कि विदेश जाकर भारत की उपलब्धियों को कमतर दिखाना उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं भारत की आर्थिक प्रगति को स्वीकार कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताने संबंधी टिप्पणी गलत है।ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर राहुल गांधी के आरोपों का भी जवाब दिया।



उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देशभर में विरोध प्रदर्शन करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं। यह भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रमाण है। गरीबी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में 50 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कांग्रेस के गरीबी हटाओ अभियान पर भी सवाल उठाए और मोदी सरकार की नीतियों की सराहना की। रिजिजू ने राहुल गांधी को सलाह दी।

हाथ जोड़कर श्रद्धालुओं का स्वागत, पैदल गश्त कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा

अयोध्या DIG सोमेन वर्मा का ये अंदाज जीत रहा सबका दिल!

अयोध्या (DKU Live ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार।पुलिस के अनेक रूप देखे होंगे, लेकिन अयोध्या में पुलिस का एक ऐसा मार्मिक और मानवीय रूप देखने को मिला, जो काफी चर्चा में है। अयोध्या रेंज के डीआईजी सोमेन वर्मा ने पुलिस बल के साथ चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग का पैदल गश्त भ्रमण कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया और सर्वसम्बंधित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। इस दौरान डीआईजी सोमेन वर्मा का अंदाज सबसे अलग नजर आया। वह 14 कोसी परिक्रमा में अयोध्या पधारे श्रद्धालुओं का हाथ जोड़कर स्वागत करते नजर आए और खुद पैदल चलकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। एक वरिष्ठ अधिकारी का श्रद्धालुओं के प्रति ये अनोखा अंदाज देखकर वहां मौजूद लोगों ने खूब सराहना की। परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं ने कहा कि पुलिस को अक्सर सख्त रूप में देखा जाता है, लेकिन डीआईजी साहब ने हाथ जोड़कर दिल जीत लिया।



आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने बिजली की मांग में भारी बढ़ोतरी से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयारी के दिए निर्देश

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। अगले छह महीनों में बिजली की मांग 14,852 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले साल की तुलना में, इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच बिजली की मांग में 18.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने बिजली की मांग में हुई अचानक बढ़ोतरी का कारण 'अल नीनो' के प्रभाव को बताया है। मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय में ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, नई परियोजनाओं की प्रगति, बिजली की



खपत पर 'अल नीनो' का असर और इसके कारण बिजली की मांग में हुई बढ़ोतरी शामिल है। इसके अलावा, मांग–आपूर्ति की स्थिति, 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर–3', 'पंपड स्टोरेज' परियोजनाओं और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जैसे विषयों पर भी बातचीत हुई। चर्चा का मुख्य केंद्र विशाखापत्तनम में आयोजित 'भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) पार्टनरशिप समिट' के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में मिले निवेश और इन परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के उपायों पर भी रहा। अधिकारियों ने बताया कि 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर–3' के तहत आंध्र प्रदेश में लगभग 21,838 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ा पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। यह ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 47 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के ट्रांसमिशन में मदद करेगा। राज्यभर में कुल 36,050 मेगावाट क्षमता वाली 'पंपड स्टोरेज' परियोजनाओं की योजना है। पोलावरम क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं के लिए 27 संभावित स्थानों की पहचान की गई है, जिनका लक्ष्य 36,050 मेगावाट बिजली पैदा करना है। जून 2024 से अब तक ऊर्जा क्षेत्र में 103 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 4.20 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

संपादकीय

चुनाव डंडा ना बने

बेशक, लोकतंत्र में चुनाव जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सर्व–प्रमुख माध्यम होते हैं, लेकिन संवाद और सहमति भी लोकतंत्र के उतने ही बड़े स्तंभ हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग कर देखना समस्याग्रस्त नजरिया है। लद्दाख में स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा ने नया राजनीतिक तनाव खड़ा कर रखा है। सरकार ने तीन–स्तरीय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है, लेकिन लद्दाख के प्रमुख राजनीतिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) जैसे संगठनों ने चुनाव स्थगित करने की मांग की है। लेकिन उनसे सहमति बनाने के प्रयास के बजाय सरकार ने सख्ती का रास्ता चुना है। लद्दाख प्रशासन ने चुनाव अवधि के दौरान लेह और कारगिल में रैलियों, धरनों, प्रदर्शनों और अन्य सार्वजनिक जमावड़ों पर पाबंदियां लगा दी हैं। लद्दाख में सिविल सोसायटी के प्रमुख नेता सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया है कि उन्हें ष्हाउस अरेस्टष जैसी स्थिति में रखा गया है। वांगचुक, एलएबी और केडीए की मांग है कि चुनाव के पहले लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के तहत संरक्षण, पूर्ण राज्य का दर्जा, विधानसभा के गठन, और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं भूमि संबंधी अधिकारों की गारंटी दी जाए। इन मुद्दों पर इन संगठनों की केंद्र के साथ बातचीत चलती रही है, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। केंद्र ने इनसे बातचीत की, तो उससे जाहिर है कि उसने इन संगठनों को लद्दाखी जनमत के एक वैध प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे में अधूरी बातचीत के बीच चुनाव कराने का क्या तर्क है, इसे समझना कठिन है। बेशक, लोकतंत्र में चुनाव जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सर्व–प्रमुख माध्यम होते हैं, लेकिन संवाद और सहमति भी लोकतंत्र के उतने ही बड़े स्तंभ हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग कर देखना समस्याग्रस्त नजरिया है। अतरू सरकार को समझना चाहिए कि जनमत के एक बड़े हिस्से को नजरअंदाज कर चुनाव थोपना इस महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डंडा बना देना है। अतीत में भी कुछ राज्यों में तत्कालीन सरकारों ने ऐसा नजरिया अपनाया था, लेकिन उसके नतीजे अच्छे नहीं रहे। लद्दाख में चुनावों की घोषणा के बीच यह खबर भी सामने आई है कि स्थानीय स्तर पर दर्जनों प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। जब कभी ऐसा बड़े पैमाने पर ऐसा होता है, तब चुनाव से उभरने वाले जनादेश पर वाजिब सवाल खड़े होते हैं।

81 साल बाद फिर इतिहास दोहराने की तैयारी, महाशक्तियों की मेज पर तय होगी दुनिया की नई तकदीर



नीरज

दुनिया के इतिहास में एक बार फिर ऐसा क्षण आने जा रहा है, जब तीन महाशक्तियों के नेता एक साथ बैठकर वैश्विक सत्ता संतुलन की नई इबारत लिखने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक को इसी वजह से श्याल्टा 2.0श कहा जा रहा है। यह महज तीन राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात नहीं है, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश है जिसमें यूक्रेन से लेकर ताइवान, ईरान से लेकर हिंद–प्रशांत और परमाणु हथियारों से लेकर विश्व व्यापार तक के भविष्य पर फैसला हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन मिलकर दुनिया को अपने–अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की तैयारी कर रहे हैं? क्या छोटे देशों की संप्रभुता और उनकी स्वतंत्र विदेश नीति तीन महाशक्तियों की सौदेबाजी की भेंट चढ़ सकती है? साथ ही क्या ट्रंप अपने दो पुराने प्रतिद्वंद्वियों के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्हें ऐसी कूटनीतिक चाल में फंसाने जा रहे हैं, जिसका असली निशाना चीन और रूस दोनों होंगे? देखा जाये तो याल्टा 2.0 को समझने के लिए 1945 के इतिहास में लौटना जरूरी है। हम आपको याद दिला दें कि 4 से 11 फरवरी 1945 तक क्रीमिया के याल्टा में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन एक साथ बैठे थे। उस समय द्वितीय विश्वयुद्ध अपने अंतिम चरण में था। जर्मनी की हार लगभग निश्चित हो चुकी थी, लेकिन युद्ध के बाद यूरोप का राजनीतिक नक्शा कैसा होगा, यह सबसे बड़ा सवाल था। उस समय तीनों नेताओं ने जर्मनी के भविष्य, पूर्वी यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था, सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते किए थे। जर्मनी और बर्लिन को मित्र देशों के कब्जे वाले क्षेत्रों में बांटने की व्यवस्था बनी। सोवियत संघ को पूर्वी यूरोप में व्यापक प्रभाव मिला। पोलैंड के भविष्य और एशिया में सोवियत हितों पर भी सहमति बनी। याल्टा सम्मेलन की सबसे विवादास्पद विरासत यह रही थी कि युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुत्व का रास्ता खुला और छोटे देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में उलझ गई। आगे चलकर यही तनाव शीतयुद्ध की बुनियाद बना। अब 81 साल बाद दुनिया के सामने लगभग वैसी ही परिस्थिति खड़ी दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1945 में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ एक साथ बैठे थे, जबकि 2026 में अमेरिका, चीन और रूस की तिकड़ी वैश्विक शक्ति संतुलन पर चर्चा करने जा रही है। देखा जाये तो इस बैठक का सबसे गंभीर पहलू यूक्रेन युद्ध है। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ऐसा समझौता हो, जिससे रूस को यूक्रेन में अपने कब्जे वाले क्षेत्रों और रणनीतिक हितों पर बढ़त मिल सके। उनकी कोशिश यह भी हो सकती है कि यूक्रेन और यूरोप को बातचीत के निर्णायक मंच से बाहर रखा जाए। यही वह स्थिति है जिससे यूरोप और कीव चिंतित हैं। यदि अमेरिका और रूस यूक्रेन के भविष्य पर आपसी समझौता करते हैं, तो यह 1945 के याल्टा की याद दिलाएगा, जब पूर्वी यूरोप की नियति तय करने में वहां के देशों की भूमिका सीमित रह गई थी। वहीं ट्रंप के सामने भी राजनीतिक चुनौती है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़ी कूटनीतिक सफलता दिखानी है। लेकिन क्या वह पुतिन को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर कर पाएंगे या रूस को अपने कब्जे वाले क्षेत्रों पर वैधता हासिल करने का अवसर मिलेगा? यही इस बैठक की असली परीक्षा होगी। साथ ही ट्रंप की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा चीन को परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की बातचीत में शामिल करना है। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है। ट्रंप चाहते हैं कि नई संधि ा में चीन भी शामिल हो। लेकिन जिनपिंग इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होंगे। अमेरिका और रूस के पास चीन की तुलना में कई गुना अधिक परमाणु हथियार हैं। बीजिंग का मानना है कि पहले दोनों बड़ी परमाणु शक्तियां अपने हथियार कम करें, उसके बाद चीन को समान प्रतिबंधों में शामिल करने की बात हो। इसलिए ट्रंप का परमाणु प्रस्ताव चीन पर रणनीतिक दबाव बनाने का हथियार भी है। इसके अलावा, ट्रंप की मनीला यात्रा और वहां हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को चुनौती देने वाली कूटनीतिक गतिविधियां इस बैठक को और दिलचस्प बनाती हैं। एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप उसी चीन की धरती पर जिनपिंग और पुतिन के साथ बैठकर वैश्विक समझौते की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन ट्रंप को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिनपिंग और पुतिन के बीच रणनीतिक साझेदारी पहले से काफी मजबूत है। आज दोनों नेताओं की अलग से हो रही बैठक भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। रूस को चीन का आर्थिक सहयोग चाहिए और चीन को रूस की ऊर्जा तथा सामरिक साझेदारी। साथ ही याल्टा 2.0 का असली खतरा यही है कि कहीं दुनिया के छोटे और मध्यम देश फिर से महाशक्तियों की सौदेबाजी के मोहरे न बन जाएं। 1945 में याल्टा ने शीतयुद्ध की जमीन तैयार की थी। 2026 का शेनझेन सम्मेलन अगर किसी नए वैश्विक शक्ति विभाजन की शुरुआत करता है, तो उसका असर आने वाले कई दशकों तक दिखाई दे सकता है। बहरहाल, फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि तीनों नेता दुनिया को बांटने का कोई समझौता करने जा रहे हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की यह मुलाकात केवल कूटनीतिक तस्वीरों तक सीमित नहीं रहेगी। दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि इस बैठक से कौन अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करके निकलता है और कौन दूसरे की बिछाई बिसात पर मोहरा बन जाता है।

सोनिया ने प्रेम लिखा, हमने राजनीति पढ़ी

श्रुति व्यास

सोनिया गांधी ने शबिलॉन्गिंग्च में भारत से अपने जुड़ाव की कहानी लिखी है। राजीव के संग धड़के अपने दिल को याद किया है। फिर उस प्रेम के सहारे एक अनजान देश में आने, उसमें रचने–बसने, उसके सुख–दुख को अपनी साँसों में उतारने की कहानी कही है। मगर जिस स्त्री ने इतने वर्षों बाद अपने प्रेम, संकोच, उलझनों, दुख और स्मृतियों को शब्द दिए, उसकी अपनी कहानी पीछे छूट गई है। और लोग अपने–अपने आग्रह–पूर्वाग्रह से राय बना रहे हैं। बाल की खाल निकाल रहे हैं। किताब अभी आई ही है कि हिसाब लग रहा है। इससे किसे फायदा होगा, किसे नुकसान? किस प्रसंग से कांग्रेस को लाभ मिलेगा, किस खुलासे से भाजपा को हमला करने का मौका मिलेगा? किस स्मृति से राहुल गांधी की छवि बनेगी और किस चुप्पी से सोनिया गांधी को कठघरे में खड़ा किया जा सकेगा? किताब के पन्ने खुले नहीं कि दशकों पुरानी स्मृतियाँ ब्रेकिंग न्यूज बन गईं। पुस्तक के अंशों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। भौकाल है, बिक्री है, राजनीतिक शोर है। बस उस स्त्री की कहानी सुनने, उसे महसूस करने की फुरसत नहीं है, जिसने इतने वर्षों बाद अपनी कहानी खुद कही है। दरअसल, भारत कभी तय नहीं कर पाया कि सोनिया गांधी को क्या माने। उन्हें अपनाया भी, उन पर संदेह भी किया। उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुँचाया, तो बदनाम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दशकों से यह बहस चलती रही कि वे सचमुच भारत की अपनी हैं भी या नहीं। इसमें एक विचित्र विडंबना है। जिस देश में विवाह के बाद स्त्री को पति के परिवार का हिस्सा मान लिया जाता है, उसी देश में सोनिया गांधी का उस परिवार और देश से जुड़ाव हमेशा सवालों के घेरे में रहा। हालाँकि किसी दूसरी संस्कृति, दूसरे परिवेश में विवाह करके जाने वाली स्त्री जानती है कि नए संसार का अपना होना इतना आसान नहीं होता। उसमें समय लगता है। स्नेह और सामंजस्य से, उन रीति–रिवाजों को अपनाने से, जिन्हें कोई समझाता नहीं, और उन अपेक्षाओं को पूरा करने से, जिन्हें कोई खुलकर बताता नहीं। कभी–कभी किसी अपने को खोने के बाद ही उस संसार से रिश्ता गहरा होता है। इसीलिए मैंने सोनिया गांधी की आत्मकथा शबिलॉन्गिंग्च उनकी राजनीति को समझने के लिए नहीं उठाई। उस बारे में तो वर्षों से पढ़ती आई हूँ। किताब उठाने का कारण उसके मुखपृष्ठ पर छपी एक युवती की आँखें थीं। कुछ खोजती हुईं, कुछ सोचती हुईं आँखें। मैं जानना चाहती थी कि कभी वह दुनिया उन्हें कैसी दिखाई देती थी। जब वे प्रेम में थीं और नहीं जानती थीं कि आगे क्या होने वाला है। इतने वर्षों बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने मन की बातें कहने का फैसला किया? अपनी उलझनों, संकोचों, इच्छाओं और दुखों को, भले कुछ ही सही, दूसरों के सामने खोलना चाहा? मैं समझना चाहती थी कि बार–बार अपनी दुनिया को बिखरते देखना कैसा होता है। और हर बार उसके टुकड़ों को समेटकर फिर जीवन बनाना कैसे संभव होता है? वह जीवन, जिसमें प्रेम है, अपनों को खोने का दुख है, स्मृतियाँ हैं और लगातार यह तलाश है कि आखिर अपना कौन है, अपना घर कहाँ है। शायद मुखपृष्ठ की वे आँखें ही इस किताब का असली आकर्षण हैं। राजीव गांधी के कैमरे से ली गई सोनिया की श्वेत–श्याम तस्वीर। एक युवती, जिसके जीवन पर अभी इतिहास ने अपना दावा नहीं किया था। चेहरे पर सहजता है, अपने होने का आत्मविश्वास है। आँखों में कुछ खोजने, कुछ जानने की उत्सुकता है। और कोमलता के भीतर एक दृढ़ता भी झलकती है। किताब पलटिए। पिछले आवरण पर फिर सोनिया हैं। मगर कई दशक बाद की। इस बार तस्वीर उनके पोते ने ली है। रंगीन तस्वीर में वे खुलकर मुस्करा रही हैं। ऐसी आत्मीय मुस्कान, जिसमें न संकोच है, न किसी को कुछ जताने की कोशिश। मानो जीवन से अब कोई शिकायत नहीं। दोनों तस्वीरों को साथ देखिए। पहली में एक युवती अपने खयालों में खोई हुई है। आगे की दुनिया से बेखबर। दूसरी में वही स्त्री है, जिसने उस दुनिया को जी लिया है। प्रेम किया, परिवार बसाया, अपनों को खोया, सत्ता को करीब से देखा और ऐसे आघात सहे, जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर भी चेहरे पर सहज मुस्कान है। मानो जिंदगी ने जो दिया, जो छीना, उसके बाद अब किसी को कुछ साबित करना बाकी नहीं रहा। और इन दो तस्वीरों के बीच? एक पूरी जिंदगी है। ऐसी जिंदगी जिसे भारत ने दशकों तक देखा। उसके हर कदम पर राय बनाई। कभी अपनाया, कभी ठुकराया। उसके फैसलों की चीरफाड़ की, उसके इरादों पर संदेह किया। यहाँ तक कि उसकी निजी जिंदगी भी देश की राजनीतिक बहसों का हिस्सा बन गई। मगर अजीब है कि जिस चेहरे को भारत इतने वर्षों से जानता है।

भारत समिट के नाम पर मोदी विरोध का षड़यंत्र

ललित

लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसमें सत्ता से असहमति के लिए पर्याप्त स्थान होता है। सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उसके निर्णयों पर प्रश्न उठाना और जनता के सामने वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण रखना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार ही नहीं, लोकतांत्रिक दायित्व भी है। लेकिन जब किसी चुनी हुई सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी राजनीतिक शक्तियों को मंच उपलब्ध ा कराया जाने लगे और देश के आंतरिक लोकतांत्रिक प्रश्नों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का विषय बनाया जाए, तब सवाल केवल राजनीतिक नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, संप्रभुता और लोकतांत्रिक मर्यादा से जुड़ जाता है। हैदराबाद में 13–14 नवंबर 2026 को आयोजित 'भारत समिट' इसी कारण राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया। कांग्रेस और तेलंगाना सरकार इसे वैश्विक चुनौतियों–जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक न्याय, निवेश, लोकतंत्र और विकास पर विमर्श का अंतरराष्ट्रीय मंच बता रही हैं। दूसरी ओर भाजपा ने सम्मेलन में कुछ विदेशी वक्ताओं की टिप्पणियों को आधार बनाकर इसे 'एंटी–भारत समिट' तक कहा है। दोनों पक्षों के अपने राजनीतिक तर्क हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक अधिक गंभीर प्रश्न उभरता है–क्या भारत की आंतरिक राजनीति में विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप को सामान्य लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा मान लिया जाना चाहिए? वैसे भी लोकतंत्र में सत्ता का विरोध हो, लेकिन राष्ट्रहित की कीमत पर नहीं। यह प्रश्न किसी एक दल के पक्ष या विपक्ष में खड़े होकर नहीं, बल्कि राष्ट्रहित की कसौटी पर विचार करने की मांग करता है। विदेशी विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और लोकतांत्रिक चिंतकों को भारत में आमंत्रित करना अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। भारत सदियों से 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना में विश्वास करता आया है। दुनिया के साथ संवाद भारतीय सभ्यता की शक्ति है। जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक अर्थव्यवस्था, युद्ध, शांति और मानवाधिकार जैसे विषय किसी एक देश की सीमाओं में बंद नहीं रह सकते। ऐसे विषयों पर अंतरराष्ट्रीय संवाद आवश्यक है। समस्या वहां शुरू होती है, जहां वैश्विक संवाद राजनीतिक प्रचार का माध्यम बन जाए और विदेशी राजनीतिक व्यक्तियों से भारत की निर्वाचित सरकार, चुनाव प्रक्रिया अथवा देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ऐसे आरोप लगवाए जाएं, जिनका प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत न किया गया हो। हैदराबाद सम्मेलन में इतालवी समाजवादी नेता जियाकोमो फिलिबेक की कथित टिप्पणी ने इसी विवाद को जन्म दिया। राहुल गांधी की उपस्थिति में भारतीय चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाने और 'वोट चोर–गद्दी छोड़' जैसे राजनीतिक नारे से जुड़ा प्रसंग इस बहस को और तीखा बना गया। यहां मूल प्रश्न यह नहीं है कि किसी विदेशी नागरिक को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राय रखने का अधिकार है या नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए वह राय रख सकता है। प्रश्न यह है कि क्या भारत की घरेलू राजनीतिक लड़ाई में विदेशी राजनीतिक नेताओं को सक्रिय पक्षकार बनाया जाना चाहिए? लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन जनता करती है, विदेशी शक्तियां नहीं। यदि किसी भारतीय राजनीतिक दल को लगता है कि चुनाव व्यवस्था में कोई कमी है, तो उसके पास संसद है, न्यायपालिका है, निर्वाचन आयोग है, मीडिया है और सबसे बड़ी शक्ति–भारत की जनता है। वह चुनाव परिणामों को चुनौती दे सकता है, न्यायालय जा सकता है, प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है और जनता के बीच अभियान चला सकता है। लेकिन यदि वह अपने राजनीतिक आरोपों को पुष्ट करने के लिए विदेशी राजनीतिक मंचों एवं विदेशी राजनेताओं का सहारा लेने लगे, तो इससे अंततः उसकी अपनी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता कमजोर होती है। यहां कांग्रेस से एक गंभीर प्रश्न पूछा जाना चाहिए–क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास इतना कमजोर हो गया है कि अपने राजनीतिक आरोपों को प्रमाणित करने के लिए विदेशी आवाजों की आवश्यकता पड़ने लगी है? और यही प्रश्न भाजपा से भी पूछा जाना चाहिए। हर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को 'भारत विरोधी' या हर आलोचना को 'विदेशी साजिश' बताना भी लोकतांत्रिक परिपक्वता नहीं है। भारत इतना विशाल और आत्मविश्वासी लोकतंत्र है कि वह आलोचना से डरकर नहीं, बल्कि तथ्यों और तर्कों से उसका उत्तर दे सकता है। विदेशी अतिथि की अनुचित टिप्पणी का विरोध होना चाहिए, लेकिन हर असहमति को राष्ट्रविरोध की संज्ञा देना भी उचित नहीं। इस विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय हित को घरेलू दलगत राजनीति से अलग रखने की परंपरा कमजोर होती दिखाई दे रही है। विदेश नीति किसी कांग्रेस, भाजपा या किसी अन्य राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं होती। वह 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सरकारें आती–जाती हैं, लेकिन राष्ट्र स्थायी रहता है। भारत



ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की परंपरा से लेकर आज की बहुध्रुवीय विश्व–व्यवस्था तक हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की पहचान बनाए रखी है। उसने अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, अरब देशों, अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण–सभी के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंध बनाए हैं। ऐसे देश के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू राजनीतिक मतभेदों को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा न बनाया जाए। सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं है। लेकिन सरकार का विरोध करने के लिए विदेशी राजनीतिक शक्तियों को भारत की आंतरिक राजनीति में सक्रिय भूमिका देना निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। इसी अंतर को समझना आज भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ यह नहीं कि देश में विपक्ष समाप्त हो जाए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है–विचार अलग हों, राजनीतिक दल अलग हों, सरकार और विपक्ष एक–दूसरे की तीखी आलोचना करें, लेकिन भारत के हित, भारत की संप्रभुता और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति मूल प्रतिबद्धता साझा रहे। यदि किसी राजनीतिक दल को सत्ता में वापसी करनी है तो उसे जनता के बीच जाना होगा। उसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, युवा, महिला सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर अपना वैकल्पिक मॉडल देना होगा। केवल यह कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, पर्याप्त नहीं। लोकतंत्र पर खतरे का दावा प्रमाण मांगता है। चुनावी पराजय का उत्तर विदेशी मंच नहीं, जनविश्वास होता है। इसी तरह सरकार और सत्तारूढ़ दल को भी आत्ममंथन करना चाहिए।

40 अरब डॉलर की डील, फिर भी पेरिस के हाथ में रहेगा रिमोट कंट्रोल

अभिनय

राफेल फ्रेंच भाषा का शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है हवा का तेज झोंका। लेकिन पाकिस्तान व उसके वजीर–ए–आला के लिए इसका अर्थ है डर का तेज झोंका। राफेल एक रात के भीतर कई बार पाकिस्तान के पूरे चक्कर लगा सकता है और इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक तहलका भी मचा सकता है। राफेल विमान का लगातार 12 घंटे तक उड़ान भरने का रिकॉर्ड है। लगातार 12 घंटे तक आसमान में उड़ान भरने का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले इसी महाबली लड़ाकू विमान के बेड़े को और विशाल बनाने के लिए भारत अब 114 नए राफेल जेट खरीदने की तैयारी में है। करीब 35 से 40 अरब डॉलर (लगभग 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक) का यह सौदा भारतीय रक्षा इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी डील साबित होने जा रही है, जिससे अकेले फ्रांस की अर्थव्यवस्था (ळक्द्ध) को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। हालांकि, इस ऐतिहासिक करार की चमक के बीच एक बड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। फ्रांस ने तकनीक हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) के मामले में अपनी श्लक्ष्मण रेखाश खींचते हुए साफ कर दिया है कि विमान के सबसे संवेदनशील पुर्जे भारत में नहीं बनेंगे। फ्रांसीसी अखबार श्द डेली एंटरप्राइजेजश की रिपोर्ट ने इस पर मुहर लगाते हुए दो टूक लिखा है कि पेरिस किसी भी कीमत पर राफेल की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को नहीं सौंपेगा। राफेल लड़ाकू विमान और इसके शक्तिशाली ड88 इंजन के भारत में निर्माण को लेकर फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों का रुख बिल्कुल साफ है। भारत में केवल विमानों को जोड़ने का काम होगा, लेकिन इनकी मुख्य और संवेदनशील तकनीक पूरी तरह फ्रांस के ही कब्जे में रहेगी। फ्रांसीसी मीडिया की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, राफेल बनाने वाली कंपनी श्डसॉल्टश और इसका इंजन तैयार करने वाली कंपनी श्सफ्रानश अपने पुराने फैसले पर अडिग हैं। गौरतलब है कि इसी साल 13 फरवरी को सफ्रान के सीईओ ओलिवियर एंड्रीस ने दो टूक कहा था कि भारत में ड88 इंजन की असेंबली लाइन तो जरूर स्थापित की जाएगी, लेकिन इंजन के सबसे अहम और कोर हिस्से फ्रांस से बाहर किसी भी देश को नहीं दिए जाएंगे। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों फ्रांसीसी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का ढांचा तो खड़ा करेंगी, मगर इसका पूरा नियंत्रण (कंट्रोल सिस्टम) पेरिस से ही चलेगा। विमान का मूल डिजाइन, बेहद संवेदनशील पुर्जे और इंजन के क्रिटिकल कंपोनेंट्स भारत में नहीं बनाए जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो, हर वह तकनीक जिस पर नियंत्रण होना जरूरी है, उसे फ्रांस अपने पास ही सुरक्षित रखेगा। फ्रांसीसी अखबार ने इस पूरे समीकरण का निचोड़ निकालते हुए लिखा है कि भविष्य में राफेल विमान का कुछ हिस्सा भले ही भारतीय फैक्ट्रियों में तैयार हो जाए, लेकिन यह मूल रूप से एक ऐसा फाइटर जेट ही बना रहेगा, जिसके विकास और अपग्रेड की लगाम हमेशा पेरिस के हाथों में रहेगी। 5 जून 2025 को हस्ताक्षरित चार प्रोडक्शन ट्रांसफर समझौतों में फ्यूजलेज (विमान के मुख्य ढांचे) के आगे, बीच और पूरे पिछले हिस्से के साथ–साथ पिछले पार्श्व (साइड) शेल शामिल हैं। इससे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को उन एयरफ्रेम संरचनाओं के निर्माण में भूमिका मिलेगी, जिन पर डसॉल्ट की विस्तार योजनाएं टिकी हैं। हैदराबाद स्थित सुविधा केंद्र से वित्तीय वर्ष 2028 में इन हिस्सों का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। आगे चलकर, यहाँ हर महीने दो पूर्ण फ्यूजलेज बनाने की क्षमता विकसित हो जाएगी। इस उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आगे के चरणों में भी उसी गति से काम होना चाहिए, ताकि अंततः तैयार विमान मिल सकें। भारत और



फ्रांस में एक साथ उत्पादन होने से डसॉल्ट को मुख्य संरचनाओं के लिए एक दूसरा स्रोत मिल जाएगा। इससे राफेल की पूरी सप्लाई चेन पर दबाव कम हो सकता है, क्योंकि भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के ऑर्डर के लिए निर्माण क्षमता को लेकर प्रतिस्पर्धा रहती है। हैदराबाद में फ्यूजलेज का निर्माण होने से स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को लड़ाकू विमानों की मुख्य संरचनाओं के लिए आवश्यक गुणवत्ता और मानकों की समझ मिलेगी। इससे ऐसी औद्योगिक क्षमताएं विकसित होंगी जो भविष्य के उत्पादन कार्यों में भी मूल्यवान साबित हो सकती हैं, भले ही विमान के डिजाइन और परिभाषा पर नियंत्रण डसॉल्ट के पास ही रहे। टाटा, डसॉल्ट द्वारा तैयार किए गए रेखाचित्रों (ड्रॉइंग्स) के अनुसार काम करेगा। सार्वजनिक समझौतों के तहत, तकनीकी परिभाषाओं पर अंतिम अधिकार फ्रांसीसी कंपनी (डसॉल्ट) के पास है। इसलिए, विमान के आयामों, सामग्रियों या निर्माण प्रक्रियाओं में भारतीय पक्ष की ओर से कोई भी बदलाव, इन समझौतों में दी गई शर्तों के दायरे से बाहर होगा और इसके लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। इन विमानों की खरीद की प्रक्रिया अब श्जरूरत की मंजूरीश से आगे बढ़कर, 2026 में फ्रांसीसी प्रस्ताव के मूल्यांकन के चरण में पहुंच गई है। भारत की श्कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीश (ब्बै) द्वारा किसी अंतिम अनुबंध को मंजूरी दिए जाने से पहले, अब कमर्शियल शर्तों, निर्माण व्यवस्थाओं और दीर्घकालिक औद्योगिक प्रतिबद्धताओं पर तत्काल निर्णय लिया जाना बाकी है। मिग–21 के रिटायर होने के बाद, भारतीय वायु सेना में स्क्वाड्रन की कमी के कारण इस प्रस्ताव को जल्द पूरा करना जरूरी हो गया है। वायु सेना को न केवल अपने लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ानी है, बल्कि उन इकाइयों के लिए कर्मियों, प्रशिक्षण और रखरखाव की क्षमता को भी बनाए रखना है, जो पहले से ही भारत की वायु रक्षा जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। फ्रांस से मिलने वाले शुरुआती विमानों के जरिए इन्हें शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जबकि हैदराबाद में इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। हालांकि, इन शुरुआती विमानों की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि डिलीवरी के समय प्रशिक्षित क्रू, ग्राउंड स्टाफ, हथियार और रखरखाव के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। सिंगल–सीट और ट्विन–सीट राफेल का प्रस्तावित मिश्रण, सेना की तैयारी की समय–सीमा को भी प्रभावित करता है। लगभग 88 सिंगल–सीट और 26 ट्विन–सीट विमानों का यह अनुपात तय करेगा कि विस्तार के दौरान, सेना किस तरह से विमानों को कन्वर्जन ट्रेनिंग और ऑपरेशनल यूनिट्स में बांटती है। प्रस्तावित बेड़े में मुख्य रूप से राफेल थ4 शामिल होने की उम्मीद है।

जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के 68 निरीक्षकों के तबादले

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। गाजीपुर और चंदौली में 68 निरीक्षकों का तबादला किया गया है। पुलिस स्थापना बोर्ड की संस्तुति के बाद यह आदेश जारी हुआ। निरीक्षकों को उनके गृह जिले को ध्यान में रखते हुए दूसरे जिलों में भेजा गया है। सूची के मुताबिक, जौनपुर से 35 निरीक्षकों को चंदौली और गाजीपुर भेजा गया है। गाजीपुर से 25 निरीक्षकों का तबादला जौनपुर और चंदौली किया गया है। वहीं, चंदौली से 8 निरीक्षकों को जौनपुर और गाजीपुर भेजा गया है। आदेश पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश और पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद जारी हुआ। तबादलों को क्षेत्रीय स्तर पर बने पुलिस स्थापना बोर्ड ने मंजूरी दी। सूची में निरीक्षकों के नाम, पीआईएस नंबर, गृह जिला और तबादले वाले जिले का विवरण है। जौनपुर से तबादला किए गए निरीक्षकों में संतोष कुमार सिंह, तेज बहादुर सिंह, सतीश कुमार सिंह, रोप कुमार शुक्ला, दिनेश कुमार सिंह, हरिनाथ प्रसाद भारती, दीपेन्द्र सिंह, अवधेश प्रसाद सिंह, अरविंद कुमार पाण्डेय और विनीत राय शामिल हैं। गाजीपुर से राजेश कुमार, संतोष कुमार पाण्डेय, प्रमोद कुमार सिंह, धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय, रहमतुल्लाह खां, पवन कुमार उपाध्याय, महेंद्र सिंह, दिनेश कुमार यादव और विनोद कुमार यादव समेत कई निरीक्षकों का तबादला हुआ है। चंदौली से अनिल कुमार पाण्डेय, सुरेन्द्र कुमार यादव, गगन राज सिंह, जयबहादुर यादव, सत्यप्रकाश यादव, मुकेश कुमार तिवारी, दिलीप कुमार और रमेश यादव का तबादला किया गया है।

मेदांता लखनऊ का अत्याधुनिक लेवल-3 एनआईसीयू समय से पहले जन्मे बच्चों को दे रहा नया जीवन

27 बेड वाले लेवल-3 एनआईसीयू में समय से पहले जन्मे बच्चों और संक्रमण से जूझ रहे नवजात शिशुओं के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। साथ ही, मां और बच्चे को एक साथ रखने की सुविधा भी है क्षेत्र का पहला मदर एंड नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और ई-एनआईसीयू भी शुरू किया गया है।



ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। भारत में समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं की मृत्यु दर दुनिया के सबसे अधिक आंकड़ों में शामिल है। जन्म के बाद नवजात शिशुओं को संक्रमण से बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ ने देश के सबसे बड़े नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) में से एक का विस्तार किया है। इस एनआईसीयू की मदद से 99 प्रतिशत से अधिक नवजात शिशुओं की जान बचाने में सफलता मिली है। पिछले पांच वर्षों में यहां 3,000 से अधिक बीमार नवजात शिशुओं का इलाज कर उन्हें स्वस्थ होने के बाद घर भेजा जा चुका है। इनमें 500 से अधिक समय से पहले जन्मे बच्चे शामिल हैं। इनमें कुछ शिशुओं का जन्म के समय वजन महज 500द600 ग्राम था, जबकि कुछ का जन्म गर्भावस्था के केवल 25–26 सप्ताह में हुआ था। भारत में नवजात शिशुओं की मृत्यु के सबसे आम कारणों में समय से पहले जन्म (30द35 प्रतिशत), संक्रमण (25द30 प्रतिशत), जन्म के समय बच्चे का न रोना (20–25 प्रतिशत) और जन्मजात विकृतियां (9 प्रतिशत) शामिल हैं। मेदांता का 27 बेड वाला एनआईसीयू इन गंभीर और उच्च मृत्यु दर वाली स्थितियों से निपटने में बेहद मददगार साबित हो रहा है। यह एनआईसीयू समय से पहले जन्मे, कम वजन वाले और गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं के इलाज के लिए विशेष सुविधाओं से सुसज्जित है। यहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पड़ोसी राज्यों और यहां तक कि नेपाल से आने वाले बच्चों का भी गंभीर बीमारियों के लिए सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। समय से पहले जन्मे बच्चों और संक्रमण से जूझ रहे नवजात शिशुओं के लिए अलग–अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। इनक्यूबेटर की मदद से बच्चों के शरीर का तापमान उचित स्तर पर बनाए रखा जाता है। अस्पताल ने क्षेत्र का पहला मदर एंड नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट भी शुरू किया है, जहां डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मां और बच्चे को एक साथ रखा जा सकता है। इससे बच्चे को दूध पिलाने और उसकी देखभाल में मां की भागीदारी बढ़ती है। इसके अलावा, क्षेत्र का पहला ई–एनआईसीयू भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से किसी अन्य अस्पताल में भर्ती नवजात शिशु का इलाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेदांता के विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में किया जा सकता है। इसके साथ ही, मेदांता की विशेष सुविधाओं से लैस एनआईसीयू एंबुलेंस शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा दूसरे राज्यों से भी नवजात शिशुओं को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने में मदद करती है। कुछ नवजात शिशुओं को जन्म के समय पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में विशेष सुविधा उपलब्ध है। इस उपचार को थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया या होल बॉडी कूलिंग कहा जाता है, जिसमें एक निश्चित अवधि तक बच्चे के शरीर का तापमान कम किया जाता है। इससे मस्तिष्क को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यूबॉर्न (पीपीएचएन) से पीड़ित नवजात शिशुओं को सांस के माध्यम से नाइट्रिक ऑक्साइड देने की सुविधा भी उपलब्ध है। इस स्थिति में फेफड़ों में रक्तचाप बढ़ जाता है, जो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम या अन्य कारणों से हो सकता है। एनआईसीयू में ये सभी सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं। सांस लेने में परेशानी का सामना कर रहे बच्चों के लिए सीपीएपी, हाई–फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन और अन्य श्वसन सहायता की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एलआईएसए तकनीक के माध्यम से कुछ समय से पहले जन्मे बच्चों को एक पतली ट्यूब की मदद से दवा दी जाती है। इसके अलावा, हृदय और मस्तिष्क की जांच, नसों के माध्यम से पोषण देने तथा नवजात शिशुओं को अस्पताल लाने के लिए विशेष वाहन की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मेदांता लखनऊ के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के डायरेक्टर डॉ. आकाश पंडिता ने कहा, "समय से पहले जन्मे और बेहद कम वजन वाले बच्चों की जान बचाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे बच्चों को समय पर इलाज, लगातार निगरानी और विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। हमारा प्रयास है कि हर बच्चे की जरूरत के अनुसार उसे बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए। बच्चे के ठीक होने और उसके आगे के विकास में मां और परिवार की भागीदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।" उनके नेतृत्व में सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अभिषेक पॉल और कंसल्टेंट डॉ. अंकिता परमार की टीम नवजात शिशुओं का इलाज करती है। विभाग में माता–पिता की काउंसलिंग, कंगारू मदर केयर (केएमसी) और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी बच्चों के वजन एवं विकास की नियमित जांच की सुविधा उपलब्ध है।

पीयू में अंतर विश्वविद्यालयीय कबड्डी प्रतियोगिता में हुए कड़े मुकाबले

क्वार्टर फाइनल जीतने वाली टीमों को मिलेगा ऑल इंडिया का टिकट



ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर स्थित इनडोर स्टेडियम में चल रही पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीय कबड्डी (पुरुष) प्रतियोगिता 2026–27 के तहत गुरुवार को रोमांचक मुकाबले खेले गए। देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों की टीमों के बीच कुल 17 मैच हुए, जिसमें कई मुकाबलों का फैसला अंतिम पलों में हुआ। 21 नवंबर तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में शुक्रवार को आठ टीमों के बीच चार क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पूल–ए के मुकाबलों में बीएनएम विश्वविद्यालय ने संबलपुर विश्वविद्यालय को 37–26 से हराया। एसजी गुरु विश्वविद्यालय ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 48–39 से हराया। एसएमके विश्वविद्यालय ने एबीवी विश्वविद्यालय को 34–25 से पराजित किया। उधर त्रिपुरा और वर्दमान विश्वविद्यालय के बीच सांस रोक देने वाली टक्कर हुई, जिसमें त्रिपुरा ने 33–32 से बेहद करीबी जीत हासिल की। खेल सचिव डॉ. शेखर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। शुक्रवार को चार क्वार्टर फाइनल और चार लीग मैच खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल जीतने वाली चारों टीमें सीधे ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालयीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करेंगी। मुकाबलों के दौरान इनडोर स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहा और दर्शकों की तालियों ने खिलाड़ियों में ऊर्जा भरी। प्रतियोगिता के निदेशक सुरेश कुमार सिंह रहे। रेफरी पैनल में जेपी सिंह, शिवमुनी, जितेंद्र कुमार पटेल, धर्मेंद्र कुमार, अजीत कुमार, माया प्रसाद राय और कन्हैया बिहारी ने निष्पक्ष निर्णय दिए। इस दौरान डॉ. विजय तिवारी, रजनीश सिंह, अशोक सिंह और सतेन्द्र सिंह मौजूद रहे, जबकि खेल गतिविधियों का कुशल संचालन राजेश सिंह ने किया।

अंतर विश्वविद्यालयीय कबड्डी में हुए कड़े मुकाबले

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर स्थित इनडोर स्टेडियम में चल रही पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीय कबड्डी (पुरुष) प्रतियोगिता के तहत गुरुवार को रोमांचक मुकाबले खेले गए। देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों की टीमों के बीच कुल 17 मैच हुए, जिसमें कई मुकाबलों का फैसला अंतिम पलों में हुआ। 21 नवंबर तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में शुक्रवार को आठ टीमों के बीच चार क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।पूल–ए के मुकाबलों में बीएनएम विश्वविद्यालय ने संबलपुर विश्वविद्यालय को 37–26 से हराया। एसजी गुरु विश्वविद्यालय ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 48–39 से शिकस्त दी। वहीं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने मगध विश्वविद्यालय को 39–33 से पराजित किया। इस पूल का सबसे कड़ा मुकाबला आरआईएस और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के बीच रहा, जिसमें आरआईएस ने मात्र एक अंक के अंतर से 31–30 से जीत दर्ज की।पूल–बी में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने आक्रामक खेल दिखाते हुए पूर्णिया विश्वविद्यालय को 54–13 के बड़े अंतर से मात दी। नॉर्थ लखीमपुर विश्वविद्यालय ने मैट्स विश्वविद्यालय को 37–09 से हराया। एसएमके विश्वविद्यालय ने एबीवी विश्वविद्यालय को 34–25 से पराजित किया। उधर त्रिपुरा और वर्दमान विश्वविद्यालय के बीच सांस रोक देने वाली टक्कर हुई, जिसमें त्रिपुरा ने 33–32 से बेहद करीबी जीत हासिल की। खेल सचिव डॉ. शेखर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। शुक्रवार को चार क्वार्टर फाइनल और चार लीग मैच खेले जाएंगे। क्वार्टर फाइनल जीतने वाली चारों टीमें सीधे ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालयीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करेंगी। प्रतियोगिता के निदेशक सुरेश कुमार सिंह रहे। रेफरी पैनल में जेपी सिंह, शिवमुनी, जितेंद्र कुमार पटेल, धर्मेंद्र कुमार, अजीत कुमार, माया प्रसाद राय और कन्हैया बिहारी ने निष्पक्ष निर्णय दिए। संचालन राजेश सिंह ने किया।

सबसे शक्तिशाली नेता थी श्रीमती इंदिरा गांधी

जौनपुर। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी जौनपुर के अध्यक्ष डा0 प्रमोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन जयंती समारोह आयोजित कर पार्टी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को विश्व की सबसे ताकतवर नेता बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में गणना होती थी। वक्ताओं ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी दूरदर्शी नेता थी, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बंग्लादेश का निर्माण किया, उन्होंने भारत को परमाणु सम्पन्न देश बनाते हुए देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के एक लाख शशस्त्र सैनिकों को आत्मसमर्पण कराकर भारतीय सेना और देश को गौरवान्वित कराया, उनके निर्णय राष्ट्र की प्रगति में मील का पत्थर साबित हो रहा है। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी किसान प्रकोष्ठ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सलामत अली का पार्टी कार्यालय पर कांग्रेसियों ने माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत व अभिनंदन किया। इस मौके पर जिला सचिव इरशाद खान, राजीव निषाद,राजकुमार गुप्ता, जब्बार अली सलमानी, मुहम्मद ताहिर, प्रवेश निषाद, राजेश गौतम, इकबाल हुसैन, सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

एन0आई0 एक्ट, 1881 की धारा–138 के अन्तर्गत लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु 21 नवम्बर 2026 को आयोजित होगी विशेष लोक अदालत

जौनपुर सिविल जज सी०डि०सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर सुशील कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व कार्यपालक अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीशध्अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर सुशील कुमार शशि, के निर्देशन में एन० आई० एक्ट, 1881 की धारा–138 के अन्तर्गत लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन 21 नवम्बर 2026 को किया जा रहा है। वादकारीगण न्यायालय में आकर विशेष लोक अदालत में एन0आई0 एक्ट, 1881 की धारा 138 के मामलों का सुलह–समझौते के आधार पर निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकते है।

20 नवम्बर को विकास खण्ड परिसर मुंगराबादशाहपुर एवं 21 नवम्बर 2026 को पब्लिक इण्टर कालेज केराकत में रोजगार मेला' का आयोजन

जौनपुर। उत्तर प्रदेश "रोजगार मिशन" के अन्तर्गत वर्ष–2026 में युवाओं को उनकी शैक्षिक, तकनीकी एवं कौशल के अनुरूप अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय नौ विधानसभा क्षेत्रों में "रोजगार मेलों" का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद के विधानसभा–मुंगराबादशाहपुर में 20 नवम्बर 2026 को विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर में एवं विधानसभा–केराकत में 21 नवम्बर 2026 को पब्लिक इण्टर कॉलेज केराकत के परिसर में प्रातः 10:00 बजे से "रोजगार मेलें" का आयोजन जिला सेवायोजन कार्यालय जौनपुर के तत्वाधान में किया जा रहा रहा है। इस "रोजगार मेलें" में निजी क्षेत्र की 15 से अधिक विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों के नियोजकों के प्रतिभाग करने की संभावना है। इसमें प्रमुख रूप में श्री गनेशा कंसलटेंट मेनपावर सर्विसेज, अडानी सोलर एनर्जी लिमिटेड, एशियन इलेक्ट्रानिक्स, वर्धमान यार्न्स टेडर्स प्रा0लि0, नितिन स्प्रींग लि0, उड़ान मैनपावर सर्विस, इम्निग्रेसन सिक्योरिटी सर्विस प्रा0लि0, टी0एस0पी0एल0 ग्रुप सल्यूशन, वेरागी प्रा0लि0, फॅस्ट फलाई कार्पोरेट, पुखराज प्रा0लि0, रक्षा सिक्योरिटी सर्विस, लर्नर लि0, आर0एस0टी0 ग्रुप ऑफ सर्विस, जे0पी0 बी0एम0जी0 एम0के0 टी0प्रा0लि0, इत्यादि कम्पनियॉ के द्वारा सोलर टेक्निशियन, सुपरवाइजर, टेक्निशियन, मशीन आपरेटर, स्टोर मैनेजर, ट्रेनर्स, असिस्टेंट आपरेटर, सेल्स मैनेजर, कलेक्सन आफिसर, हेल्पर मशीन आपरेटर सहित विभिन्न पदों पर चयन किया जायेंगा। इस रोजगार मेले में स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाने के अवसर उपलब्ध कराने तथा उनकी प्रतिभा एवं कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर प्रदान करना है। जिसमें योग्यता– दसवीं, बारहवीं, उत्तीर्ण, स्नातक, आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को विभिन्न शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यताधारी युवाओं से अपील की जाती है कि इस अवसर का लाभ उठाने के लिए रोजगार संगम पोर्टल https://rojgaarsangam-up-gov-in पर अपना निःशुल्क पंजीकरण कराये तथा अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुरूप कम्पनियों में आवेदन करें। मेले में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी 20 नवम्बर एवं 21 नवम्बर 2026 को प्रातः 10:00 बजे अपने समस्त शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियों तथा आवश्यक बायोडाटा के साथ उपस्थित होकर रोजगार मेले में प्रतिभाग कर लाभान्वित होने का कष्ट करें।

7013 छूटे विद्यार्थियों को 13 दिसंबर को बांटे जाएंगे टैबलेट

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से 15 नवंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में किन्हीं कारणों से टैबलेट न पाने वाले विद्यार्थियों को अब 13 दिसंबर को डिवाइस का वितरण किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए सूचना जारी कर दी है। डिजिशक्ति योजना के नोडल समन्वयक डॉ. आरबी सिंह के अनुसार, 7013 विद्यार्थियों को दो पालियों में टैबलेट दिए जाएंगे। पहली पाली में क्रम संख्या एक से 3500 तक के विद्यार्थियों को सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक टैबलेट मिलेंगे। दूसरी पाली में क्रम संख्या 3501 से 7013 तक के विद्यार्थियों को दोपहर एक से 3:30 बजे तक डिवाइस वितरित की जाएगी। वितरण विश्वविद्यालय के पुराने परिसर स्थित परीक्षा संचालन हॉल, आर्ट्स क्वाड्रैंगल में होगा। विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होना होगा। साथ में विश्वविद्यालय का पहचान पत्र अथवा मूल अंकपत्र और आधार कार्ड लाना अनिवार्य है।



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौ न्यायिक अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी किए

लखनऊ, (संवाददाता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा और बदायूं में तैनात नौ न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए स्थानांतरण और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। 16 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार शेफाली को मथुरा में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट नियुक्त किया गया है। वह रोहित सोनी का स्थान लेंगी। रोहित सोनी को इसी पद पर बदायूं भेजा गया है, जहां वह महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। वह जयति चंद्रा का स्थान लेंगे। जयति चंद्रा को बदायूं में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) बनाया गया है।महिमा जैन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 9(2) के तहत मथुरा में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। वह रूपाली सिंह का स्थान लेंगी। रूपाली सिंह को बदायूं में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर तैनात किया गया है। वह निदा जैदी का स्थान लेंगी। निदा जैदी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 9(2) के तहत बदायूं में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। वह भारती तायल का स्थान लेंगी। भारती तायल को बदायूं में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) बनाया गया है।

एकादशी पर चमका सिंघाड़ा और कन्दा का धन्धा

जौनपुर। जगत के पालनहार भगवान विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी (देवोत्थानी एकादशी) को जागेंगे। इस मंगल अवसर पर घरों व मंदिरों में विराजे भगवान के श्रंगार व पूजन की तैयारियां लोगों ने पूरी कर ली हैं। सनातन धर्म में मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ माह की देवशयनी ग्यारस से चार माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। हिंदू रीति–रिवाज के अनुसार इस दौरान विवाह आदि शुभ कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं। भगवान का यह विश्राम कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को पूर्ण होता है। इस शुभ दिन के मौके पर घरों से लेकर मंदिरों तक भगवान का विशेष पूजन किया जाता है। शंख और घंटों की ध्वनि से भगवान को जगाया जाता है। इसके बाद भगवान को स्नान कराकर नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। देवोत्थानी एकादशी की पूर्व संध्या पर बाजारों में खासी रौनक देखने को मिली। भक्तों ने भोग लगाने के लिए गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंद, फल मिष्ठान सहित पूजन सामग्री की जमकर खरीदारी की। शहर की बाजार सहित कई स्थानों पर गन्ने बिक रहे हैं। पूजा के लिए पांच गन्ने की आवश्यकता होती है। एक गन्ना 20 रुपये का बिकता है। 100 रुपये के पांच गन्ने बाजार में बिक रहे हैं। इसके साथ ही 40 रुपये किलो सिंघाड़ा बिक रहा है। देवोत्थान एकादशी का पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में गन्ने, शकरकंद व सिंघाड़े की बिक्री हो रही है। इस दिन से मांगलिक कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे। इसके लिए बाजारों में खरीदारी करने के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है।

रोजगार मेला' 20 और 21 को

जौनपुर। 20 नवम्बर को विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर में एवं विधानसभा– केराकत में 21 नवम्बर को पब्लिक इण्टर कॉलेज केराकत के परिसर में प्रातः 10 बजे से "रोजगार मेलें" का आयोजन जिला सेवायोजन कार्यालय जौनपुर के तत्वाधान में किया जा रहा रहा है। इस "रोजगार मेलें" में निजी क्षेत्र की 15 से अधिक विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों के नियोजकों के प्रतिभाग करने की संभावना है। इसमें प्रमुख रूप में श्री गनेशा कंसलटेंट मेनपावर सर्विसेज, अडानी सोलर एनर्जी लिमिटेड, एशियन इलेक्ट्रानिक्स, वर्धमान यार्न्स टेडर्स प्रा0लि0, नितिन स्प्रींग लि0, उड़ान मैनपावर सर्विस, इम्निग्रेसन सिक्योरिटी सर्विस प्रा0लि0, टी0एस0पी0एल0 ग्रुप सल्यूशन, वेरागी प्रा0लि0, फॅस्ट फलाई कार्पोरेट, पुखराज प्रा0लि0, रक्षा सिक्योरिटी सर्विस, लर्नर लि0, आर0एस0टी0 ग्रुप ऑफ सर्विस, जे0पी0 बी0एम0जी0 एम0के0टी0प्रा0लि0, इत्यादि।

स्कॉर्पियो से कुचलने की घटना में तीसरी मौत, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में राजदेव ने तोड़ा दम

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के चक मुफ्तफाबाद में जमीनी विवाद के दौरान स्कॉर्पियो से कुचलने की घटना में घायलों में शामिल 70 वर्षीय राजदेव यादव की बुधवार की रात में मौत हो गई। गंभीर हालत में उन्हें वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है।

सीएम के गढ़ में अखिलेश का रोड शो शुरू, बाबू बंधू की प्रतिमा का करेंगे अनावरण



गोरखपुर, (संवाददाता)। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता जुटे हैं। एयरपोर्ट से चौरीचौरा तक जगह–जगह लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। पीडीए रथ के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम चल रहा है। अखिलेश यादव पीडीए रथ में सवार होकर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में कार्यकर्ता नारे लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। रथ के साथ समर्थकों की भीड़ भी चल रही है। गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र स्थित सूबा बाजार हनुमान मंदिर के पास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत की तैयारी की गई है। पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उनके पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश यादव गोरखपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव एयरपोर्ट से कुछ ही देर में बाहर निकलने वाले हैं। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में सपा और अखिलेश यादव के समर्थक उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। एयरपोर्ट गेट पर ढोल–नगाड़े बज रहे हैं। फरुआही नृत्य भी देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव के आगमन को लेकर भारी उत्साह है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उनके स्वागत के लिए कुनराघाट तिराहे पर दो क्रेन लगाई गई हैं। यहां से गुजरने पर उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी की गई है। चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगमन को लेकर गांव–गांव से रैलियां निकाली जा रही हैं। इन रैलियों में भाजपा के पुराने कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। जंगल गौरी नंबर दो उर्फ अमहिया के मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता रहे ।

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के असलहा तस्कर से पिस्टल खरीदने का आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर, (संवाददाता)। लारेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह से जुड़े असलहा तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी कैंट थाना पुलिस ने हथियार खरीदने के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र के भलुही गांव निवासी कृष्णा सिंह उर्फ काका के पास से .32 बोर की पिस्टल और एक कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ में उसने बताया कि पांच माह पहले कैंट क्षेत्र में गिरफ्तार श्रेयांश यादव से 25 हजार रुपये में पिस्टल खरीदी थी। पुलिस अब हथियार खरीदने के मकसद और उसके आपराधिक घटनाओं में इस्तेमाल की आशंका की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कृष्णा सिंह उर्फ काका के खिलाफ कुशीनगर जिले में मारपीट के दो मामले दर्ज हैं। असलहा तस्करी के मामले में श्रेयांश यादव की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस उससे हथियार खरीदने वालों की तलाश कर रही थी। इसी जांच में कृष्णा का नाम सामने आया। उसकी गिरफ्तारी से तस्करी नेटवर्क में हथियारों की खरीद–फरोख्त की एक और कड़ी जुड़ गई है। पूर्वांचल में सक्रिय लारेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह के असलहा तस्करी नेटवर्क का 14 सितंबर को पर्दाफाश हुआ था। एसटीएफ और कैंट पुलिस ने विंध्यवासिनी पार्क के पास से श्रेयांश यादव उर्फ बबलू समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से चार पिस्टल, एक रिवॉल्वर, मैगजीन और कारतूस बरामद हुए थे। पूछताछ में पता चला था कि मध्य प्रदेश के सेंधवा और हरियाणा के सोनीपत से हथियार लाकर गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महराजगंज समेत पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में सप्लाई किए जा रहे थे। कैंट थाने में दर्ज असलहा तस्करी के मुकदमे में 31 आरोपी नामजद हैं। पुलिस और एसटीएफ अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कृष्णा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच अब हथियारों की सप्लाई करने वालों के साथ ही खरीदारों पर भी केंद्रित हो गई है। पुलिस श्रेयांश से पिस्टल खरीदने वाले अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही बरामद हथियार के इस्तेमाल और कृष्णा के उसे खरीदने के पीछे की वजह का भी पता लगाया जा रहा है।

बसंतपुर खास और सेमरा में लगेंगे इलेक्ट्रिक बसों के फास्ट चार्जर

गोरखपुर, (संवाददाता)। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग सुविधा बढ़ाने के लिए शहर में दो नए स्थानों पर फास्ट (अपार्चुनिटी) चार्जर लगाए जाएंगे। नगर निगम ने बसंतपुर खास और सेमरा में इसके लिए जमीन उपलब्धा कराने पर अनापत्ति दे दी है। दोनों स्थानों पर कुल 0.418 हेक्टेयर जमीन पर चार्जिंग की सुविधा विकसित की जाएगी। इससे इलेक्ट्रिक बसों को नियमित संचालन के दौरान कम समय में चार्ज किया जा सकेगा। नगर निगम की ओर से जारी अनापत्ति के मुताबिक, बसंतपुर खास में 0.218 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, सेमरा में कुल 0.387 हेक्टेयर जमीन में से 0.200 हेक्टेयर भूमि चार्जर लगाने के लिए दी जाएगी। नगरीय परिवहन निदेशालय की पहल पर पहले महेवा एहतमाली, आराजी छावनी, नौसड़ और जंगल नकहा नंबर–दो में चार्जर लगाने के लिए अनापत्ति दी गई थी। हालांकि, परिवहन विभाग ने इन स्थलों को अनुपयुक्त बताया था। इसके बाद बसंतपुर खास और सेमरा का चयन किया गया। फास्ट चार्जर की मदद से इलेक्ट्रिक बसों को कम समय में चार्ज किया जा सकेगा। इसके लिए बसों को नियमित संचालन के दौरान बस टर्मिनल या निर्धारित चार्जिंग पॉइंट पर कुछ देर रोकना होगा। इससे बसों को पूरी तरह चार्ज होने के लिए घंटों डिपो में खड़ा नहीं करना पड़ेगा। साथ ही बसों का संचालन भी अधिक सुचारु हो सकेगा। इसके अलावा चरगावां में 4.64 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। करीब दो हजार गर्फीट क्षेत्रफल में बनने वाले इस स्टेशन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे एक साल में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यहां बसों की चार्जिंग के साथ रख–रखाव, पार्किंग, बिजली आपूर्ति और सुरक्षा की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। नगर निगम के मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नई चार्जिंग सुविधाएं शुरू होने से बसों को समय से रूट पर भेजने में सहूलियत होगी। इससे यात्रियों को भी निर्धारित समय पर बसें उपलब्ध हो सकेंगी।

बेकाबू स्कॉर्पियों ने कई लोगों को रौंदा, दो की मौत

वाराणसी, (संवाददाता)। जौनपुर जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है। एक अनियंत्रित स्कार्पियो वाहन ने कई व्यक्तियों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की जान चली गई है। दुर्घटना में घायल हुए अन्य सभी लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना जौनपुर–आजमगढ़ हाईवे स्थित गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद में हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घायलों का हाल जानने के लिए डीएम उमेश मिश्रा भी अस्पताल पहुंचे। घटना, विवाद और पंचायत के दौरान की बताई जा रही है। एएसपी अंनत चंद्रशेखर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। यह साजिश थी या हादसा दोनों मुद्दों के मद्देनजर छानबीन की जा रही है। गांव निवासी सुभाष चंद्र यादव के मुताबिक, गांव के मनोज यादव और महेंद्र यादव सगे भाई हैं। दोनों के बीच जमीन को लेकर पिछले तीन दिनों से विवाद चल रहा था। बुधवार को भी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो रही थी। मौके पर गांव के लोग जुटे हुए थे। इसी दौरान महेंद्र का बेटा हाईवे की तरफ से गाड़ी लेकर आया और बिजली के खंभे से टकरा गया। टक्कर के बाद गाड़ी पलट गई, जिससे हादसा हो गया।



विश्व शौचालय दिवस पर महापौर ने किया अत्याधुनिक शौचालय का उद्घाटन

–स्वच्छ एवं सुंदर अयोध्या के लिए नागरिक सुविधाओं का विस्तार – महापौर

अयोध्या (DKU Live ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर बुधवार को महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने नयाघाट स्थित पार्किंग परिसर में नगर निगम की ओर से नवनिर्मित अत्याधुनिक शौचालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम अधिकारियों एवं पार्षद अंकित त्रिपाठी के साथ शौचालय की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि अयोध्या अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और आस्था का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रही है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का आगमन होता है। ऐसे में नगर निगम का दायित्व है कि शहर में स्वच्छता के साथ नागरिकों और आगंतुकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। नयाघाट जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल पर अत्याधुनिक शौचालय का निर्माण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सफाई व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ और सुविधाजनक शौचालयों की उपलब्धता भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। नगर निगम अयोध्या को स्वच्छ, सुंदर और सुविधायुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने नागरिकों एवं श्रद्धालुओं से सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने और उनकी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, सहायक अभियंता राजपति यादव, सहायक नगर आयुक्त गुरुप्रसाद पांडेय, भाजपा नेता श्रीनिवास शास्त्री उपस्थित रहे।

घर की तंगी ने ननिहाल भेजा, हौसले ने नेशनल का टिकट दिलाया

गोरखपुर, (संवाददाता)। परिवार की आर्थिक तंगी ने शुभम को माता–पिता से दूर ननिहाल में रहने को मजबूर कर दिया लेकिन उसने इस मजबूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मजदूर माता–पिता के बेटे ने अभावों के बीच पढ़ाई जारी रखने के साथ ताइक्वांडो में मेहनत की और ब्लैक बेल्ट हासिल की। अब उसका चयन रांची में होने वाली अंडर–19 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जहां वह प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा। एमजी इंटर कॉलेज में 12वीं के छात्र 17 वर्षीय शुभम के पिता वीरेंद्र प्रसाद और मां लक्ष्मी देवी मजदूरी करते हैं। कुशीनगर में मंसूरगंज के पास लक्ष्मीपुर महुहवां स्थित घर में आर्थिक तंगी के कारण उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। चार भाई–बहनों में सबसे बड़ा होने के कारण परिवार को उसके भविष्य की चिंता थी। ऐसे में पिता ने बेहतर शिक्षा की उम्मीद में उसे कैंपियरगंज के जनकपुर करतहरी स्थित ननिहाल भेज दिया। अपनों से दूर रहकर पढ़ाई करने के दौरान ही शुभम ने अपने सपनों को नई दिशा दी। ननिहाल में सरकारी स्कूल में पढ़ाई के दौरान कक्षा सात में उसकी मुलाकात ताइक्वांडो प्रशिक्षक आदित्य जायसवाल से हुई। उन्होंने शुभम को इस खेल का प्रशिक्षण देना शुरू किया। वर्ष 2020 में उसे पहली येलो बेल्ट मिली। इसके बाद उसने नियमित अभ्यास जारी रखा। आर्थिक परेशानियों के बावजूद उसने मेहनत नहीं छोड़ी। लगातार अभ्यास और लगन के दम पर वर्ष 2024 में ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली। स्कूल स्तर से प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हुए शुभम ने जिला और मंडल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2025 में वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश भी गया। हाल ही में तीन से सात अक्टूबर तक सहजनवां में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उसने शानदार प्रदर्शन किया। प्रयागराज के खिलाड़ी को हराकर प्रथम स्थान हासिल किया। इसी उपलब्धि के आधार पर उसका चयन 26 से 30 नवंबर तक रांची में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। शुभम को अब कुंदन राय प्रशिक्षण दे रहे हैं। वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी में जुटा है। उसका अगला लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना और पदक जीतना है। कभी आर्थिक तंगी के चलते जिस परिवार को बेटे की पढ़ाई जारी रखने की चिंता थी। आज उसी परिवार का बेटा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में प्रदेश का मान बढ़ाने जा रहा है। शुभम का सफर उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अभावों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला रखते हैं।

सड़क किनारे मिला अज्ञात युवक का शव, 500 मीटर दूर स्कूटी बरामद, चाबी मिलने से उलझी गुत्थी



वाराणसी, (संवाददाता)। आजमगढ़ जिले के बरदह थाना क्षेत्र के जिवली में प्रयागराज– गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह एक अज्ञात युवक का क्षत–विक्षत शव मिला। शव से करीब 500 मीटर दूर एक स्कूटी बरामद हुई। स्कूटी की चाबी शव के पास मिलने से घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे सड़क हादसा मानकर जांच कर रही है। बुधवार सुबह साधन सहकारी समिति के सामने सड़क किनारे करीब 30 वर्षीय युवक का शव पड़ा था। उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था, जिससे पहचान करना मुश्किल हो रहा था। घटनास्थल के आसपास वाहनों के टायरों के निशान भी मिले। ग्रामीणों की सूचना पर थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर मदन के घर के सामने खड़ी स्कूटी बरामद की। उसका पंजीकरण नंबर गुजरात का बताया गया। हैरानी की बात यह रही कि स्कूटी की चाबी शव के पास मिली। उसके पास से कोई पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं मिले। थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। घटना सुबह चार से पांच बजे के बीच की बताई जा रही है। पुलिस ने शव और स्कूटी को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्कूटी के पंजीकरण के आधार पर उसके मालिक और मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

पोस्टमास्टर जनरल ने नवगठित डाक परिक्षेत्र के मण्डलाध्यक्षों के कार्यों की की समीक्षा

प्रयागराज, (संवाददाता)। भारतीय डाक विभाग जन–जन तक सेवाएँ पहुँचाने की अपनी समृद्ध एवं गौरवशाली विरासत को कायम रखते हुए डिजिटल युग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर स्वयं को विकसित कर रहा है। आधुनिक तकनीक एवं डिजिटल नवाचारों के समावेश से डाक सेवाओं को अधिक सुलभ, त्वरित, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाया जा रहा है, जिससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। गुजरात सर्किल में नवगठित सूरत डाक परिक्षेत्र के



अंतर्गत विभागीय गतिविधियों को गति देने, कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा करने तथा लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 17 नवंबर को पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के कांफ्रेंस हॉल में प्रथम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रवर डाक अधीक्षक यश कुमार जैन, सहायक निदेशक एस. वी. परमार सहित तमाम अधिकारियों ने पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव का स्वागत किया। पोस्टमास्टर जनरल ने सूरत प्रधान डाकघर कैंपस स्थित नव सृजित रीजनल ऑफिस का निरीक्षण कर आवश्यक दिशानिर्देश दिए। 1 नवंबर, 2026 से सृजित सूरत परिक्षेत्र में सूरत, भरूच, नर्मदा, डांग, नवसारी, तापी एवं वलसाड सहित 7 जिलों के साथ केंद्रशासित प्रदेश दमन एवं दादरा नगर हवेली शामिल हैं। इसमें 6 डाक मंडल, 6 प्रधान डाकघर, 238 उप डाकघर एवं 1561 शाखा डाकघर सहित।

लाला लाजपत राय के विचार और आदर्श आज भी राष्ट्रसेवा की प्रेरणा– राजकुमार चोपड़ा

प्रयागराज, (संवाददाता)। राजर्षि टंडन सेवा केंद्र, बैंक रोड पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं पंजाब केसरी के नाम से सुविख्यात लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर लोक सेवक मंडल द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक सेवक मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चोपड़ा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव विनीत सिंह उपस्थित रहे। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में राजकुमार चोपड़ा ने लाला लाजपत राय के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं राष्ट्र के प्रति अतुलनीय योगदान को याद करते हुए कहा कि लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे महानायक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की आजादी, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा के प्रसार और राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। श्री चोपड़ा ने विशेष रूप से उल्लेख किया ।

प्रायोगिक परीक्षाएं दस जनवरी के बाद संभावित

अयोध्या (DKU Live ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार।जनगणना के कारण यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा कराना चुनौती बन गया है। विधानसभा चुनाव के कारण पांच फरवरी से ही बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित की गई हैं। इस लिहाज से इंटरमीडिएट और हाईस्कूल (विज्ञान और गृह विज्ञान) की प्रयोगात्मक परीक्षाएं दिसम्बर से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक खत्म होनी थी। हालांकि पांच जनवरी तक जनगणना और उसके बाद फॉलोअप के कारण प्रयोगात्मक परीक्षाएं दस जनवरी के बाद प्रस्तावित की जा रही है। इस साल हाईस्कूल (विज्ञान और गृह विज्ञान) विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा फिर से शुरू होने के कारण प्रैक्टिकल में परीक्षार्थियों की संख्या तकरीबन दोगुनी हो गई है। इसी के चलते यूपी बोर्ड ने दिसंबर से प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू कर दी थी लेकिन जनगणना की तारीखें के आने के बाद पूरी कार्ययोजना पर नए सिरे से काम करना पड़ रहा है। इस बार 10वीं–12वीं में 52,11,570 छात्र–छात्राएं पंजीकृत हैं जबकि पिछले साल 53,37,432 परीक्षार्थी थे। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि जनगणना शुरू हो गयी है ऐसे में जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं दिसंबर में होनी थी वह अब दस जनवरी के बाद शुरू हो सकेंगी।

पंचकोसी परिक्रमा, अयोध्या में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, 16 जगह होंगे बैरियर

अयोध्या (DKU Live ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार।अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा को लेकर यातायात पुलिस ने आंतरिक डायवर्जन प्लान जारी किया है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर के निर्देश पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 19 नवंबर शाम 6 बजे से परिक्रमा और भीड़ समाप्त होने तक डायवर्जन लागू रहेगा। परिक्रमा मार्ग पर 16 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं। इन रास्तों पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लकड़मंडी चौराहा और दुर्गागंज माझा बैरियर से पुराने सरयू पुल की ओर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। वाहन लोलपुर बाईपास से जाएंगे। हनुमानगुफा चौराहा, लता मंगेशकर चौक और वासुदेव घाट तिराहे की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों को साकेत फ्लाईओवर और निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। आसिफबाग, विद्याकुंड, महोबरा फ्लाईओवर, टेढ़ी बाजार और साथी तिराहे पर भी यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। उदया चौराहा, गैस गोदाम तिराहा, कटरा तिराहा और राजघाट बंधा तिराहे पर भी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में 14 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। इनमें फटिकशिला आश्रम, साकेत पुल, बैकुंठ धाम, बालू घाट मल्टीलेवल पार्किंग, साथी तिराहा और उदया चौराहा प्रमुख हैं। गोंडा, बस्ती से लखनऊ जाने वाले और लखनऊ–बाराबंकी से गोंडा–बस्ती जाने वाले वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का पालन करने की अपील की है।

कोतवाली बीकापुर क्षेत्र में लूट की वारदात

अयोध्या (DKU Live ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार। अयोध्या कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के नगर पंचायत क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने प्रतिष्ठित व्यवसायी को निशाना बनाया। बदमाश व्यवसायी से 28 हजार 500 रुपये लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बदमाशों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस कार सवार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र के व्यापारियों में चिंता का माहौल है। सीसीटीवी में एक बलेनो कार नजर आई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

आग लगने पर व्यापारियों को मिले क्षतिपूर्ति - कंछल

भदोही, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल ने कहा कि जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह स्वास्थ्य बीमा और प्रतिष्ठान में आग लगने पर एक करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाए। सरकार की ओर से वसूले जाने वाले ब्याज को 18 से घटाकर 9 फीसदी की जाए। विद्युत और गृहकर की वाणिज्यिक दरों को घरेलू दरों के बराबर किया जाए। वह मंगलवार को जिले में पहुंचे। ज्ञानपुर नगर में जिलाध्यक्ष डॉ. घनश्याम दास गुप्ता के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ने से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। कहा कि व्यापारी प्रतिवर्ष अरबों रुपये का कर सरकार को देते हैं, जिससे देश की योजनाएं चलती हैं,

लेकिन उनके हित पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि एक देश–एक चुनाव, एक देश–एक टैक्स की तर्ज पर एक दुकान–एक लाइसेंस की व्यवस्था लागू की जाए। सभी विभागों के लाइसेंस 10 वर्ष का शुल्क लेकर आजीवन किया जाए। मनमानी गृहकर वृद्धि पर रोक लगाकर इसे केवल 10 फीसदी तक सीमित किया जाए। पटरी दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन बनाकर उन्हें व्यवस्थित स्थान देने की मांग की गई है। जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों की सामान्य मृत्यु पर 50 लाख रुपये की सरकारी सहायता देने की भी मांग की गई है। इस मौके पर अशोक कुमार, रमेश पासी आदि रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।